Title: Request the Government not to introduce the Uttar Pradesh Reorganisation Bill to provide a separate State of Uttrakhand as it is not listed in the list of Business.

कुंवर अखिलेश सिंह : माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की यह सरकार राज्यों का गलत तरीके से बंटवारा कर के पूरे देश को तोड़ने की साजिश कर रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तराखंड को बनाने की साजिश चल रही है और उत्तराखंड के नाम पर उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ छल करने का प्रयास किया जा रहा है। आज जब सदन का अंतिम दिन है, तो सदन के अंतिम दिन सरकार इस बिल को सदन में इंट्रोड्यूस करना चाहती है। उधम सिंह नगर, जिसमें सिख बहुल आबादी है उसको आज उत्तराखंड में शामिल करने की साजिश की जा रही है। हरिद्वार जनपद, जिसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर के उसे उत्तर प्रदेश में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है, मांग की है, उसको भी उत्तराखंड में शामिल करने की साजिश की जा रही है। आज तक सरकार ने यह तय नहीं किया है कि उत्तराखंड की राजधानी कहां होगी, लेकिन आज उत्तराखंड के नाम पर, राजनैतिक लाभ लेने के लिए, अपने राजनीतिक हित साधने के लिए सरकार उत्तराखंड विधेयक को इस सदन के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहती है। हम सब आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि यह देश को तोड़ने की साजिश है। छोटे-छोटे राज्यों का गठन कर के इस देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। इसलिए जब तक सदन को विश्वास में न लिया जाए, तब तक इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव सदन में नहीं आना चाहिए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल): सभापति महोदय, इस पर मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं। कृपया मुझे भी अपनी बात कहने की अनुमति प्रदान करें।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): सभापति जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो सदस्य यह सवाल उठा रहे हैं, जो आज का एजेंडा है, उसमें कहीं भी इस प्रकार के बिल को इंट्रोड्यूस करने की बात नहीं है और अब कोई सप्लीमेंट्री एजेंडा, आखिरी दिन, आखिरी समय में देना, मान्यता के विरुद्ध है। इसलिए वह बिल आज इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सरकार को भी समझा दीजिए कि आखिरी दिन, आखिरी समय में इस तरह का कोई बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई सप्लीमेंट्री एजेंडा न दे।

सभापति महोदय : एजेंडा में तो ऐसा है नहीं। लेकिन माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, तो बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Mr. Chairman, Sir, as per the List of Business, there is no Bill to be introduced. There is no provision for bringing any Bill for introduction today. In the List of Business, no mention is made about the introduction of any Bill. ...(*Interruptions*)

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : सभापति जी, नियमों का शिथिलीकरण करते हुए बिल पेश किए जाने की अनुमति देने का अध्यक्ष महोदय को अधिकारी है। पूर्व में भी ऐसा हुआ है।

â€¦(व्यवधान)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Sir, the only confusion that is created is about a letter written by Shri L.K. Advani to the President for the Presidential sanction of the Bill. That is the confusion. ...(*Interruptions*)

सभापति महोदय : कृपया आसन ग्रहण किया जाए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): सभापति जी, यह तो सदन को बतलाया जा सकता है कि इसकी सूचना दे दी गई है या नहीं?

सभापति महोदय : अभी तक लिस्ट के अनुसार वह सदन में प्रस्तुतीकरण के लिए नहीं है और न ही सदन को अभी तक इस बारे में कोई सूचना दी गई है।

...(व्यवधान)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : There is only a communication from the President to Shri L.K. Advani regarding this Bill. That is also not circulated.

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति जी, आदरणीय चन्द्रशेखर जी ने बहुत अहम सवाल उठाया है।â€¦(व्यवधान) आप सुन लीजिए। स्कूल में मास्टर भी इतना नहीं डांटते जितना कि आप डांटते है। आप पहले हमारी बात को सुन लीजिए। â€¦(व्यवधान)

SHRI S. JAIPAL REDDY (MIRYALGUDA): I suggest, Mr. Chairman, that you direct the Government to clarify as to whether it has any intention to bring forward a Supplementary Agenda because as of now we are not in possession of any such notice. I think when Members have raised it at this level, I think the Government should come forward with the clarification.

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, आदरणीय चन्द्रशेखर जी ने बहुत अहम सवाल उठाया। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो सवाल उठाया है, उसे सरकार जरूर गंभीरतापूर्वक ले। आज चर्चा है कि सप्लीमैंट्री एजेंड़ा में ये बिल लाए जा रहे हैं। वे आये या नहीं, हमने नोटिस दिया है। इसलिए हम अपनी भावना को आपके सामने रखना चाहते हैं। मै कहना चाहता हूं कि राजनीतिक कारणों से राज्य का बंटवारा कहीं से भी अच्छा नहीं है। बिहार राज्य के बंटवारे का जो प्रस्ताव यहां पर आ रहा है, वह राजनीतिक कारणों से आ रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कहा करते थे कि हमारी लाशों पर झारखंड बनेगा लेकिन आज उन्होंने ही प्रस्ताव पारित कराया है। इधर और उधर वाले दोनों पक्ष राजनीतिक कारणों से अलग राज्य की बात कर रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब तक राज्य की जनता की भावना का सही ढंग से विश्लेाण नहीं कर लिया जाये कि आखिर राज्य की जनता राज्य के बंटवारे के पक्ष में है या नहीं तब तक कोई बिल इस सदन में नहीं आना चाहिए। अगर आप अलग राज्य का दावा करना चाहते हैं तो जो उत्तर बिहार और मध्य बिहार बचा है, उसके लिए आप क्या विशे पैकेज देने जा रहे हैं? उस विशे पैकेज में यह अवधि भी

निश्चित होनी चाहिए कि कितने दिनों में केन्द्र सरकार उस पैकेज को पूरा करेगी। अगर यह नहीं होता है तो हम यह कहेंगे कि जनता की भावनाओं का आदर होना चाहिए और यह बिल इस सदन में नहीं आना चाहिए।